

यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला-पाली) राज 0

न अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वाद पत्र संख्या : 10/2022

No. : 2022/18

वार्दी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

तहसीलदार, जैतारण

लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार

तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. अर्गतकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह कौम चारण  
निवासी खिनावड़ी

2. पोकरराम पुत्र धोकलराम कौम कुमावत  
निवासी निमाज

3. भूण्डाराम पुत्र मुकनाराम कौम कुमावत  
निवासी बिरोल

4. रामेश्वरलाल पुत्र भीकाराम कौम घांची  
निवासी जैतारण

5. लीला देवी पत्नी मदनलाल कौम सरगरा  
निवासी जैतारण।

राजस्व वाद पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम,

1955

तारीख रजु :- 14.01.2022

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

2. श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, सुरेश चौधरी, किशोर कुमावत अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक :- 22.03.2022

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 72/9 कुल रकबा 0.3642 हैक्टर किस्म बाराणी दोयम, मौजा जैतारण में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 05 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर वाणिज्यिक उपयोग (दुकान, चार दीवारी आदि निर्माण) कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए बिनाय मुख्रासमत दिनांक 10.01.2022 को पैदा हुआ जब भू. अ.निरीक्षक ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से अकृषि (वाणिज्यिक प्रयोजन) का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,  
जैतारण, जिला-पाली

इस पर वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या से 5 ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसाल किया गया, जवाब दावा में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित अनुसार आराजी खसरा संख्या 72/9 रकबा 1642 हैक्टर यानि 02-05 बीघा किरग बरानी दोयम की भूमि मौज जैतारण तहसील जैतारण में स्थित है। पश्चातवर्ती प्रकर्म राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार दिनांक 17.11.1991 से पूर्व बस्सी आवासीय क्षेत्र के मामलो में प्रार्थी के आवेदन पत्र पर नगर हल्का जैतारण ने प्रकरण संख्या 297 वर्ष 2012-13 कायम करते हुए राजस्थान भू स्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के तहत रामेश्वरलाल पुत्र भीकाराम की उक्त खसरा संख्या 72/9 की भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में लिए जाने बाबत प्रस्तुत निवेदन पर बाद जांच उक्त प्रकरण को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त खसरा संख्या 72/9 के सम्पूर्ण रकबे की भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण कर दिया एवं रामेश्वरलाल द्वारा आवश्यक शुल्क भी जमा करवा दिया गया। वादग्रस्त खसरा संख्या 72/9 के सम्पूर्ण रकबे की भूमि को भू-रूपान्तरण किये जाने के बाद नगरपालिका जैतारण ने राजस्व रिकॉर्ड माफिक आदेश के नामान्तरणकरण करने हेतु तहसीलदार जैतारण को जरिए पत्र क्रमांक 1.पा.जे./2018/2104-05 दिनांक 07.08.2018 को पत्र जारी किया था। जिसकी वादी तहसीलदार जैतारण द्वारा आज दिन तक पालना नहीं की गई है एवं अपने पदीय कर्तव्यो की पालना करने में तहसीलदार जैतारण पूर्णरूपेण असफल रहे है। तत्पश्चात रामेश्वरलाल स्वयं ने माफिक भू-रूपान्तरण आदेश की नामान्तरण की कार्यवाही करने हेतु वादी तहसीलदार जैतारण को दिनांक 05.03.2020 को अपनी ओर से पुनः एक आवेदन पत्र पेश किया था जो उसी दिन वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी को भेजा गया जिसकी भी आज दिन तक कोई पालना नहीं हुई एवं हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने अनावश्यक रूप से तहसीलदार जैतारण के मार्फत यह कार्यवाही पेश करवायी है जो कतई गलत है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि वास्ते आवासीय प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण हो चुकी है एवं वर्तमान में उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं रही है उसके बावजूद भी वादी तहसीलदार जैतारण एवं उसके अधीनस्थ कार्मिको ने रामेश्वरलाल व जवाब देहन्दा को तंग व परेशान करने की नियत से झूठा प्रकरण बनाते हुए एवं झूठे साक्ष्य एवं सबूत तैयार कर अदालत श्रीमान के समक्ष यह निराधार कार्यवाही पेश की है जो काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। साथ ही इस प्रकरण में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किए जाने बाबत भी निवेदन है। इस प्रकार से उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं रहने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। वादी पक्षकार इस प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। इस वादपत्र में वर्णित भूमि भू-रूपान्तरण सुदा होने से कृषि भूमि नहीं रही है। वादी को जवाब देहन्दा के विरुद्ध कोई बिनाय वाद प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा में कथन किया कि वाणिज्यिक उपयोग (दूकान, चारदीवारी आदि निर्माण) प्रतिवादी संख्या 1 के नहीं है। तथा इस निर्माण में प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। इसलिए वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे।



बहस वादी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,  
जैतारण, जिला-पाली

लोकन किया गया। बहस पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन निर्णयन निम्नानुसार है-

वादी तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण खातेदारान् द्वारा ग्राम जैतारण स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 72/9 रकबा 0.3642 हैक्टर किरम बाराणी पम जो कि कृषि भूमि है पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किरम परिवर्तित कर गैरकृषि उपयोग (दुकान, चार दीवारी आदि निर्माण) कर खुर्द बुर्द कर रहे है तथा टीनेन्सी शर्तों का भंग किया गया है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर खातेदारान् को मौके बेदखल किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थी खातेदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का खसरा संख्या 72/9 रकबा 0.3642 हैक्टर नगरपालिका जैतारण के सक्षम अधिकारी द्वारा करण संख्या 297/2012-2013 अन्तर्गत धारा 90ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है। तथा भू रूपान्तरण उपरान्त नगरपालिका जैतारण द्वारा राजस्व रिकर्ड में नामान्तकरण दर्ज किए जाने हेतू पत्र क्रमांक न.पा.जे./2018/2104-05 दिनांक 07.08.2018 जारी किया गया था लेकिन उक्त संपरिवर्तन आदेश के अनुरूप नामान्तकरण दर्ज नहीं होने के कारण भू अभिलेख में वादग्रस्त आराजी अभी भी कृषि भूमि दर्ज है। जिसके आधार पर तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध यह दावा प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है।

3. जवाबदावे के साथ प्रस्तुत भू रूपान्तरण आदेश एवं अन्य दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका जैतारण द्वारा आदेशांक/न.पा.जे./2018/2104-05 दिनांक 07.08.2018 द्वारा वादग्रस्त आराजी को गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्रदान करते हुए अभिधृति अधिकारी को निर्वापित किया जा चुका है। अतः वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नहीं होने के कारण प्रतिवादी के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही संधारणीय नहीं है। अतः हस्तगत वादपत्र विधिविरुद्ध होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-पत्र अंतर्गत धारा-177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
पदेन सहायक कलक्टर,  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,  
जैतारण, जिला-पाली  
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
पदेन सहायक कलक्टर,  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,  
जैतारण, जिला-पाली  
(जिला-पाली)



निर्णय आज दिनांक 22/03/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।